



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9]  
No. 9]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 1986/पौष 13, 1907  
NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 1986/PAUSA 13, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1986

अधिसूचनाएँ

सांकांनि० 11(अ) :—निम्नलिखित नियम जो संसद सदस्य  
वैतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 (1954 का 30) की धारा  
9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति द्वारा केन्द्रीय सरकार  
से परामर्श करने के पश्चात् उक्त धारा की उपधारा (3) के खण्ड (च)  
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये गये हैं तथा जिनका  
राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा उक्त धारा  
की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अनुमोदन और पुष्टि कर दी गई है,  
सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किये जाते हैं :—

संसद-सदस्य (निर्वाचन-क्षेत्र संबंधी भत्ता) नियम, 1986

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त  
नाम संसद सदस्य (निर्वाचन-क्षेत्र संबंधी भत्ता) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्वाचन-क्षेत्र संबंधी भत्ते की रकम :—कोई सदस्य, संसद सदस्य  
वैतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा  
8 के अधीन एक हजार दो सौ पचास रुपये प्रति मास की दर से  
निर्वाचन-क्षेत्र संबंधी भत्ता पाने का हकदार होगा।

3. निर्वाचन-क्षेत्र संबंधी भत्ता अन्य भत्तों आदि के अतिरिक्त होगा—  
शंकाओं को दूर करने के लिये, यह घोषित किया जाता है कि इन नियमों

के अधीन अनुज्ञेय निर्वाचन संबंधी भत्ता, तत्समय प्रवृत्त किन्हीं अन्य  
नियमों के अधीन अनुज्ञेय किन्हीं अन्य भत्तों या सुविधाओं के (चाहे वह  
नकद हो या वस्तु रूप में) अतिरिक्त होगा न कि उनके अन्वीकरण में।

4. निरसन—संसद सदस्य (अतिरिक्त सुविधा) नियम, 1975  
इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं।

[फा०सं० 2/1/एम एस ए/85]

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 3rd January, 1986

NOTIFICATIONS

G.S.R. 11(E).—The following rules which have  
been made by the Joint Committee constituted under  
sub-section (1) of section 9 of the Salary, Allowances  
and Pension of Members of Parliament Act, 1954  
(30 of 1954), after consultation with the Central  
Government, in exercise of the powers conferred on  
it by clause (f) of sub-section (3) of the said section,  
and have been approved and confirmed by the Chair-  
man of the Council of States and the Speaker of the  
House of the People, as required by sub-section (4)  
of that section, are published for general informa-  
tion :—

THE MEMBERS OF PARLIAMENT (CONSTITU-  
TUENCY ALLOWANCE) RULES, 1986.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Members of Parliament (Constituency Allowance) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amount of Constituency allowance.—A member shall be entitled to receive the constituency allowance under section 8 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), at the rate of rupees one thousand two hundred and fifty per mensem.

3. Constituency allowance to be in addition to other allowances, etc.—For the avoidance of doubts, it is hereby declared that the constituency allowance admissible under these rules shall be in addition to, and not in derogation of, any other allowances or facilities admissible (whether in cash or in kind) under any other rules for the time being in force.

4. Repeal.—The Members of Parliament (Additional Facilities) Rules, 1975 are hereby repealed.

[F. No. 2/1/MSA/85]

सांका०नि० 12(अ) :—निम्नलिखित नियमों को, जिन्हें संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति ने उक्त धारा की उपधारा (3) के खण्ड (च) द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् बनाया है और जिन्हें उस धारा की उपधारा (4) द्वारा यथापेक्षित रूप में राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष ने अनुमोदित और पुष्ट कर दिया है, सामान्य जानकारी के लिये प्रकाशित किया जा रहा है :—

संसद सदस्य (वाहन क्रय अग्रिम) नियम, 1986

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संसद सदस्य (वाहन क्रय अग्रिम) नियम, 1986 है।

(2) ये सजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. अग्रिम की अधिकतम रकम :—(1) वह अधिकतम रकम जो किसी सदस्य को वाहन खरीदने के लिये उधार दी जा सकेगी, बीस हजार रुपये या उस वाहन की, जिसे खरीदने का विचार है, वास्तविक कीमत से, इन में से जो भी कम है, अधिक नहीं होगी :

परन्तु ऐसी किसी दशा में जिसमें वाहन पहले ही खरीदा जा चुका हो और उसका पूरा भुगतान कर दिया गया हो अग्रिम की कोई रकम अनुज्ञेय नहीं होगी :

परन्तु यह और कि जहां यह भुगतान भागतः किया गया हो, वहां अग्रिम की रकम सदस्य द्वारा यथा प्रमाणित, भुगतान की जाने वाली शेष राशि तक ही सीमित होगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन अग्रिम की रकम राष्ट्रपति के नाम में मंजूर की जायेगी और अधिप्रमाणित (आदेश और अन्य लिखित) नियम, 1958 के उपबन्धों के अनुसार अधिप्रमाणित की जायेगी।

3. अग्रिम का प्रतिसंदाय :—(1) नियम 2 के अधीन दिये गये अग्रिम और उस पर ब्याज की वसूली संबंधित सदस्य के वेतन बिल से अधिक से अधिक साठ बराबर मासिक किस्तों में की जायेगी जिनकी अवधि सदस्य के कार्यकाल से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यदि अग्रिम लेने वाला सदस्य ऐसा चाहे तो राज्य सभा का सभापति अथवा लोक सभा का अध्यक्ष, यथास्थिति, अग्रिम की वसूली कम्प-किस्तों में अनुज्ञात कर सकता है।

स्पष्टीकरण :—मासिक किस्तों में वसूल की जाने वाली अग्रिम की रकम पूरे-पूरे रूपों में नियत की जायेगी सिवाय अन्तिम किस्त के, जब शेष बकाया रकम, जिसमें रुपये की भिन्न भी है, वसूल की जाये।

(2) अग्रिम की वसूली उसके लिये जाने के बाद दिये जाने वाले पहले वेतन से शुरू होगी।

(3) उक्त अग्रिम पर साधारण ब्याज, केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिये वाहन अग्रिम पर निर्धारित दर पर लिया जायेगा।

(4) यदि कोई सदस्य अग्रिम का पूर्णतः प्रतिसंदाय किये जाने से पूर्व अपनी सदस्यता छोड़ देता है तो शेष बकाया राशि, उस पर ब्याज सहित तुरन्त केन्द्रीय सरकार को एक मुश्त राशि में संदत्त की जायेगी।

4. वाहन का विक्रय :—उस दशा के सिवाय जब कोई सदस्य, सदस्य नहीं रहता है, सदस्य अग्रिम की महायता से क्रय किये गये वाहन के विक्रय के लिये केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी लेगा, यदि ऐसा अग्रिम उस पर उद्भूत ब्याज सहित पूर्णतः प्रतिसंदात नहीं कर दिया गया है।

(2) जहां कोई सदस्य उक्त वाहन का अन्तरण किसी अन्य सदस्य को करना चाहता है, वहां उसे उस वाहन से सम्बद्ध दायित्व का पश्चात् कथित सदस्य को अन्तरण करने के लिये केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन अनुज्ञात किया जा सकेगा :

परन्तु यह तब जब वाहन खरीदने वाला सदस्य यह घोषणा अभिलिखित करे कि उसे इस बात का पता है कि उसे अन्तरित वाहन बंधक किया हुआ है और वह उसके निबन्धनों और उपबन्धों से आवद्ध है।

(3) उन सभी मामलों, जहां किसी वाहन का विक्रय, उसके क्रय के लिये लिये गये अग्रिम और उस पर ब्याज का पूर्णतः प्रतिसंदाय किये जाने से पूर्व किया जाता है, वहां विक्रय आगम का उपयोग, जहां तक आवश्यक हो, ऐसे शेष बकाया के प्रतिसंदाय के लिये किया जाना चाहिये :

परन्तु जब वाहन का विक्रय इस दृष्टि से किया जाता है कि दूसरा वाहन खरीदा जा सके, तब केन्द्रीय सरकार विक्रय आगम का ऐसी खरीद के लिये उपयोग किये जाने के लिये सदस्य को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञात कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) शेष बकाया रकम नये वाहन की लागत से अधिक नहीं होने दी जायेगी;

(ख) शेष बकाया रकम का पूर्व नियत दर पर प्रतिसंदाय किया जाता रहेगा; और

(ग) नये वाहन का बीमा भी करवाया जायेगा और उसे केन्द्रीय सरकार के पास बंधक किया जायेगा।

5. अवधि जिसके भीतर वाहन खरीदने के लिये बातचीत पूरी की जा सकेगी।

अग्रिम लेकर वाहन खरीदने वाला सदस्य वाहन खरीदने की बातचीत पूरी करके उनका अंतिम संदाय अग्रिम लेने की तारीख से एक मास के भीतर करेगी और ऐसी बातचीत पूरी करके संदाय करने में असफल रहने पर, लिये गये अग्रिम की पूरी रकम, उस पर एक मास के ब्याज सहित केन्द्रीय सरकार को सदस्य द्वारा वापस कर दी जायेगी।

6. करार का निष्पादन :—(1) अग्रिम लेते समय सदस्य प्ररूप 1 में एक करार निष्पादित करेगा और खरीद पूरी होने पर वह अग्रिम

के लिये प्रतिभूति के रूप में उक्त वाहन केन्द्रीय सरकार को आडमान करले हुए प्ररूप 2 में एक बंध पत्र निष्पादित करेगा।

(2) वाहन की कीमत प्ररूप 2 में बंधपत्र के साथ संलग्न विनिर्देशों की अनुसूची में प्रविष्ट की जायेगी।

7. वेतन और लेखा अधिकारी को प्रमाण-पत्र—(1) जब कोई अग्रिम लिया गया हो, तब मंजूरी प्राधिकारी, यथास्थिति, राज्य सभा या लोक सभा के वेतन और लेखा अधिकारी को इस आशय का एक प्रमाणपत्र भेजेगा कि अग्रिम लेने वाले सदस्य ने प्ररूप 1 में करार पर हस्ताक्षर कर दिये हैं और वह ठीक पाया गया है।

(2) मंजूरी प्राधिकारी यह देखेगा कि वाहन की खरीद अग्रिम लेने की तारीख से एक मास के भीतर की जाती है और वह प्राधिकारी सदस्य द्वारा सम्यक रूप से निष्पादित बंध पत्र को अन्तिम रूप से रिकार्ड किये जाने से पूर्व यथास्थिति, राज्य सभा या लोक सभा के वेतन और लेखा अधिकारी को उसकी परीक्षा के लिये तत्काल प्रस्तुत करेगा।

8. बंध पत्र की सुरक्षित अभिरक्षा और उसका रद्द किया जाना—

(1) बंध पत्र मंजूरी प्राधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा।

(2) जब अग्रिम का पूर्णतः प्रतिसंदाय कर दिया गया हो, तब अग्रिम और उस पर ब्याज के पूर्ण प्रतिसंदाय के बारे में, यथास्थिति, राज्य सभा या लोक सभा के वेतन और लेखा अधिकारी से प्रमाण पत्र अग्रिमप्राप्त करने के पश्चात्, बंधपत्र सम्यक्तः रद्द किया जाकर संबंधित सदस्य को वापस कर दिया जायेगा।

9. वाहन का बीमा—अग्रिम से खरीदे गये वाहन का अग्नि, चोरी और दुर्घटना से पूरी हानि के लिये बीमा कराया जायेगा और बीमा पालिसी में (प्ररूप III के रूप में) एक खंड होगा जिसके द्वारा बीमा कंपनी वाहन को ऐसी हानि या नुकसान की बाबत, जिसकी प्रतिपूर्ति मरम्मत, यथापूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की जाती है, संदेय किन्हीं राशियों का संदाय स्वामी के बजाय केन्द्रीय सरकार को करने के लिये करार करती है।

प्ररूप 1

(नियम 6 देखिए)

वाहन खरीदने के लिए अग्रिम लेने समय निष्पादित किए जाने वाले करार का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री \_\_\_\_\_, जो संसद सदस्य हैं (जिन्हें इसमें आगे उधार लेने वाला कहा गया है और इसके अंतर्गत उनके वारिस, प्रशासक, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशित भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे केन्द्रीय सरकार कहा गया है) के बीच आज तारीख \_\_\_\_\_ को किया गया ;

उधार लेने वाले ने वाहन खरीदने के लिए संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन बनाए गए उन नियमों के उपबन्धों के अधीन जिनमें संसद सदस्यों को वाहन के क्रय के लिए अग्रिम मंजूर करने का विनियमन किया गया है, वाहन खरीदने के लिए \_\_\_\_\_ रु. (\_\_\_\_\_ रुपए) उधार दिए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन किया है और केन्द्रीय सरकार उधार लेने वालों को उक्त रकम इसमें आगे दिए गए उपबन्धों और शर्तों पर देने के लिए सहमत हो गई हैं ;

इसके पक्षकारों के बीच यह करार किया जाता है कि उधार लेने वाले को केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई \_\_\_\_\_ रु. (\_\_\_\_\_ रुपए) की राशि (जिसकी प्राप्ति उधार लेने वाले ने

इसके द्वारा अभिस्वीकार की है) के प्रतिफलस्वरूप उधार लेने वाला केन्द्रीय सरकार के साथ यह करार करता है कि वह (1) उक्त नियमों के अनुसार संगणित ब्याज सहित उक्त रकम का केन्द्रीय सरकार को संदाय अपने वेतन में से प्रतिमास कटौती कराके करेगा, जैसा कि उक्त नियमों द्वारा उपबन्धित है और ऐसी कटौतियां करने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्राधिकृत करता है। और (2) इस विलेख की तारीख से एक मास के भीतर उक्त उधार की पूरी रकम वाहन खरीदने में व्यय करेगा या, यदि उसके द्वारा संसद वास्तविक कीमत उधार की रकम से कम है तो, शेष रकम केन्द्रीय सरकार को तुरन्त वापस कर देगा और उधार लेने वाले को पूर्वोक्त रूप में उधार दी गई रकम और उस पर ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त वाहन को केन्द्रीय सरकार के पक्ष में आडमान रखने वाला दस्तावेज उक्त नियमों द्वारा उपबन्धित प्रारूप में निष्पादित करेगा।

अन्त में यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि यदि इस विलेख की तारीख से एक मास के भीतर वाहन नहीं खरीदा जाता है और आडमान नहीं रखा जाता है या, यदि उधार लेने वाला उक्त अवधि के भीतर दिवालिया हो जाता है या सदस्य नहीं रहता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उधार की पूरी रकम और उस पर प्रोद्भूत ब्याज शीघ्र और संदेय हों जाएंगे।

इसके साथ स्वरूप उधार लेने वाले ने ऊपर सर्वप्रथम लिखी तारीख को इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

उक्त श्री \_\_\_\_\_ ने उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

प्ररूप 2

(नियम 6 देखिए)

वाहन के लिए बन्धक-पत्र का प्ररूप

यह करार एक पक्षकार के रूप में श्री \_\_\_\_\_ (जिन्हें इसमें आगे "उधार लेने वाला" कहा गया है और इसके अंतर्गत उनके वारिस, प्रशासक, निष्पादक, विधिक प्रतिनिधि और समनुदेशित भी हैं) और दूसरे पक्षकार के रूप में भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें इसमें आगे केन्द्रीय सरकार कहा गया है) के बीच आज तारीख \_\_\_\_\_ को किया गया।

उधार लेने वाले ने वाहन खरीदने के लिए संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के अधीन बनाए गए, संसद सदस्यों को वाहन के क्रय के लिए अग्रिम मंजूर करने से संबंधित नियमों के अनुसार (जिन्हें इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है) वाहन खरीदने के लिए \_\_\_\_\_ रु. (\_\_\_\_\_ रुपए) उधार दिए जाने के लिए आवेदन किया है और उसे वह मंजूर कर दिया गया है, और उधार लेने वाले को जिन शर्तों पर अग्रिम दिया गया है / दिया गया था उनमें से एक शर्त यह है/थी कि उधार लेने वाला उसे उधार दी गई रकम के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त वाहन केन्द्रीय सरकार को आडमान रखेगा और उधार लेने वाले ने पूर्वोक्त रूप में उधार दी गई रकम से या उसके भाग से वाहन खरीदा है, जिसकी विशिष्टियां इसके नीचे लिखी अनुसूची में दी गई हैं।

यह विलेख इस बात का साक्षी है कि उक्त करार के अनुसरण में और पूर्वोक्त प्रतिफल के लिए उधार लेने वाला यह प्रसंविदा करता है कि वह पूर्वोक्त \_\_\_\_\_ रु. की राशि या उसके उस अतिशेष का जो इस विलेख की तारीख को असंदात रह जाता है \_\_\_\_\_ रु. (\_\_\_\_\_ रुपए) की समान किस्तों में प्रत्येक मास के प्रथम दिन संदाय करेगा और उस



समय शीघ्र और देय रह गई राशि पर उक्त नियमों के अनुसार संगणित ब्याज का संदाय करेगा और उधार लेने वाला यह करार करता है कि ऐसी किस्ते उक्त नियमों द्वारा उपबन्धित रीति से उसके वेतन में से मासिक कटौतियाँ करके वसूल कर ली जाएँ और उक्त करार के अनुसरण में उधार लेने वाला वाहन का, जिसकी विविष्टियाँ नीचे लिखी अनुसूची में उपबन्धित हैं, उक्त अग्रिम और उस ब्याज के लिए प्रतिभूति के रूप में उक्त नियमों द्वारा यथा अपेक्षित, केन्द्रीय सरकार को समनुदेशन और अन्वरण करता है।

उधार लेने वाला यह करार करता है और यह घोषणा करता है कि उसने उक्त वाहन के क्रय की पूरी कीमत का संदाय कर दिया है और वह उसको आत्यन्तिक सम्पत्ति है और उसने उसे गिरवी नहीं रखा है और जब तक उक्त अग्रिम के सबंध में कोई घनराशि केन्द्रीय सरकार को संदेय रहती है तब तक वह उक्त वाहन का विक्रय नहीं करेगा, उसे गिरवी नहीं रखेगा और उसमें अपने स्वत्व या कब्जे को नहीं छोड़ेगा, परन्तु सदैव यह है और यह करार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि यदि मूलधन या ब्याज की उक्त किस्तों में से कोई किस्त देय हो जाने के पश्चात् दस दिन के भीतर नहीं दी जाती है या पूर्वोक्त रूप में वसूल नहीं की जाती है तो या, यदि उधार लेने वाले की मृत्यु हो जाती है या वह किसी समय सदस्य नहीं रहता है या, यदि उधार लेने वाला उक्त वाहन का विक्रय कर देता है या उसे गिरवी रख देता है या उसमें अपने स्वत्व अथवा कब्जे को छोड़ देता है या वह दिनालियाँ हो जाता है या अपने लेनदारों के साथ कोई समझौता या ठहाराव कर लेता है या यदि कोई व्यक्ति उधार लेने वाले के विरुद्ध किसी विधि या निर्णय के निष्पादन में कार्यवाही आरम्भ कर देता है तो उक्त मूलधन की पूरी राशि जो उस समय देय हो किन्तु जिसका संदाय न किया गया हो, उस पर पूर्वोक्त रूप से संगणित ब्याज सहित, तुरन्त संदेय हो जाएगी और इसके द्वारा यह करार किया जाता है और घोषणा की जाती है कि इसमें इसके पूर्व उल्लिखित घटनाओं में से किसी घटना के होने पर केन्द्रीय सरकार

उक्त वाहन का अभिग्रहण कर सकेगी और उसे कब्जे में ले सकेगी और या तो उसको हटाए बिना उस पर कब्जा रख सकेगी या उसे हटा सकेगी और सार्वजनिक नीलामी द्वारा या प्राइवेट मविदा द्वारा उक्त वाहन का विक्रय कर सकेगी और विक्रय में प्राप्त धनराशि में से उक्त उधार का उस समय असंदेह रह गया शेष भाग और पूर्वोक्त रूप में संगणित और उस पर देय ब्याज और इसके अधिन अपने अधिकारों को बनाए रखन, उनकी रक्षा करने या उन्हें प्राप्त करने में उचित रूप से किए गए सब खर्च, प्रभार, व्यय आर सदायों की राशि अपने पास प्रतिधारित रख सकेगी और यदि कोई घनराशि ग्राप रहती है तो उसे उधार लेने वाले, उसके निष्पादको, प्रशामको, या वैयक्तिक प्रतिनिधियों को दे देगी, परन्तु यह और कि उक्त वाहन का कब्जा लेने या उसका विक्रय करने की पूर्वोक्त शक्ति से उधार लेने वाले या उसके वैयक्तिक प्रतिनिधियों पर उक्त शेष देय रह गई रकम आर ब्याज के लिए या, यदि वाहन का विक्रय किया जाता है तो उतनी रकम के लिए केन्द्रीय सरकार के वाद लाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जितनी में विक्रय में प्राप्त शुद्ध आगम देय रकम से कम रह जाते हैं, और उधार लेने वाला यह करार भी करता है कि जब तक कोई घनराशि केन्द्रीय सरकार को शीघ्र और देय रहती है तब तक उधार लेने वाला उक्त वाहन का अग्नि, चोरी या दुर्घटना से हानि या नुकसान के विरुद्ध ऐसी बीमा कम्पनी में जिसका सर्वाधन महालेखाकार द्वारा अनुमोदन किया जाए, बीमा कराएगा और बीमा चालू रखेगा तथा महालेखाकार के समाधानप्रद रूप में इस बात का साक्ष्य पेश करेगा कि उस मोटर बीमा कम्पनी को, जिसमें उक्त मोटर वाहन का बीमा कराया गया है वह मूचना मिल चुकी है कि उस पालिसी में केन्द्रीय सरकार (भारत के राष्ट्रपति) हितवद्ध है और उधार लेने वाला यह करार भी करता है कि वह उक्त वाहन को नष्ट या क्षतिग्रस्त नहीं करने देगा या नहीं होने देगा या उसमें व्यक्तिगत टूट-फूट से अधिक टूट-फूट नहीं होने देगा और यदि उक्त वाहन को कोई नुकसान पहुंचता है या उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उधार लेने वाला उसकी तुरन्त मरम्मत कराएगा और उसे ठीक करा लेगा।

अनुसूची

वाहन का वर्णन  
निर्माता का नाम  
वर्णन  
सिलेंडरों की संख्या  
इंजन सं.  
चौसस सं.  
लागत कीमत

इसके साक्ष्यस्वरूप इसमें ऊपर लिखे तारीख को उक्त (.....) ने और भारत के राष्ट्रपति के लिए और, नक़्क़ और से .....  
उधार लेने वाले का नाम

..... ने इस पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

उक्त.....

1. ....

2. ....

(साक्षियों के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनके और से

..... ने

(नाम और पदनाम)

1. ....

2. ....

(उधार लेने वाले के हस्ताक्षर  
और पदनाम)

(अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम)

(साक्षियों के हस्ताक्षर)

की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए

उधार लेने वाले का नाम और पदनाम -----

प्रारूप-3

(अनयम 9 देखिए)

बीमा पालिसियों में जोड़े जाने वाले खंड का प्रारूप

1. यह घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि श्री----- (वाहन का स्वामी, जिसे इसमें आगे इस पालिसी की अनुसूची में बीमाकृत कहा गया है) ने वाहन केन्द्रिय सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को उस अग्रिम के लिए प्रतिभूति के रूप में आडमान कर दिया है जो उस वाहन के खरीदने के लिये लिया गया है। यह भी घोषणा की जाती है और करार किया जाता है कि उक्त सरकार (राष्ट्रपति) ऐसे धन में हितबद्ध है जो यदि यह पृष्ठांकन न होता तो उक्त श्री----- (इस पालिसी के अधीन बीमाकृत) को उक्त वाहन का हानि या उसको हुए नुकसान का बाबत (जिस हानि या नुकसान का प्रतिपूर्ति मरम्मत, यथापूर्वकरण या प्रतिस्थापन द्वारा नहीं की गई है) संदेय होता। ऐसा धन सरकार (राष्ट्रपति) को उस समय तक दिया जाएगा जब तक कि वह वाहन का बंधकदार है और उसकी रसाद इस बात का प्रमाण होगी कि ऐसा हानि या नुकसान का बाबत कंपनी ने पूरा और अंतिम भुगतान कर दिया है।

2. इस पृष्ठांकन द्वारा अभिव्यक्त रूप से जो करार किया गया है उसके सिवाय इसकी किसी भी बात से बीमाकृत के या कंपनी के, इस पालिसी के अधीन या संबंध में अधिकारों या दायित्वों का अथवा इस पालिसी के किसी निबंधन, उपबंध या शर्त का न तो उपांतरण होगा और न उस पर प्रभाव पड़ेगा।

[फ। स. 2/1/एमएसए/85]

G.S.R. 12(E).—The following rules which have been made by the Joint Committee constituted under sub-section (1) of section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), after consultation with the Central Government, in exercise of the powers conferred on it by clause (ff) of sub-section (3) of the said section, and have been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required by sub-section (4) of that section, are published for general information :—

#### THE MEMBERS OF PARLIAMENT (ADVANCE FOR THE PURCHASE OF CONVEYANCE) RULES, 1986.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Members of Parliament (Advance for the Purchase of Conveyance) Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Maximum amount of advance.—(1) The maximum amount which may be advanced to a member for the purchase of a conveyance shall not exceed rupees twenty thousand or the actual price of the conveyance, which is intended to be purchased, whichever is less;

Provided that no advance shall be admissible when a conveyance has already been purchased and paid for in full;

Provided further that where such payment has been made in part, the amount of advance shall be limited to the balance to be paid as certified by the member.

(2) The amount of advance under sub-rule (1) shall be sanctioned in the name of the President and

authenticated in accordance with the provisions of the Authentication (Orders and other Instruments) Rules, 1958.

3. Repayment of Advance.—(1) Recovery of the advance granted under rule 2, together with interest thereon, shall be made from the salary bill of the member concerned in not more than sixty equal monthly instalments, which shall not extend beyond the tenure of his membership.

Provided that where the member receiving the advance so desires, the Chairman of the Council of States or the Speaker of the House of the People, as the case may be, may permit recovery of the advance to be made in lesser number of instalments.

Explanation.—The amount of the advance to be recovered monthly shall be fixed in whole rupees, except in the case of last instalment when the remaining balance including any fraction of a rupee shall be recovered.

(2) The recovery of advance shall commence with the first issue of salary after the advance is drawn.

(3) Simple interest at the rate fixed by the Central Government in relation to advance for purchase of conveyance by Government servants shall be charged on the said advance.

(4) Where a member ceases to be such a member before the full repayment of the advance, the outstanding balance, together with interest thereon, shall be paid to the Central Government immediately in one lump sum.

4. Sale of conveyance.—(1) Except when a member ceases to be such a member, previous sanction of the Central Government shall be obtained for the

sale by the member of the conveyance purchased with the aid of an advance, if such advance, together with the interest accrued thereon, has not been fully repaid.

(2) Where a member wishes to transfer the said conveyance to another member, he may be permitted, under the orders of the Central Government, to transfer the liability attaching to that conveyance to the latter member provided that the member purchasing the conveyance records a declaration that he is aware that the conveyance transferred to him remains subject to the mortgage bond and that he is bound by its terms and provisions.

(3) In all cases where a conveyance is sold before the advance received for its purchase, together with interest thereon, has been fully repaid, the sale-proceeds must be applied, so far as may be necessary, towards the repayment of such outstanding balance.

Provided that when the conveyance is sold only in order that another conveyance may be purchased, the Central Government may permit the member to apply the sale proceeds towards such purchase, subject to the following conditions, namely :—

- (a) the amount outstanding shall not be permitted to exceed the cost of the new conveyance;
- (b) the amount outstanding shall continue to be repaid at the rate previously fixed; and
- (c) the new conveyance shall also be insured and mortgaged to the Central Government.

5. Period within which negotiations for purchase of conveyance may be completed.—A member who draws an advance for the purchase of a conveyance shall complete his negotiations for the purchase of, and pay finally for, the conveyance within one month of the date on which he draws the advance and failing such completion of negotiations and final payment, the full amount of the advance drawn, together with interest thereon for one month, shall be refunded by the member to the Central Government.

6. Execution of agreement.—(1) At the time of drawing the advance, the member shall execute an agreement in Form I, and on completing the purchase, he shall further execute a mortgage bond in Form II hypothecating the conveyance to the Central Government as security for the advance.

(2) The cost price of the conveyance shall be entered in the schedule of specifications attached to the mortgage bond in Form II.

7. Certificate to the Pay and Accounts Officer.—

(1) When an advance is drawn, the sanctioning authority shall furnish to the Pay and Accounts Officer of the Council of States or, as the case may be, of the House of the People, a certificate that the Agreement in Form I has been signed by the member drawing the advance and that it has been found to be in order.

(2) The sanctioning authority shall see that the conveyance is purchased within one month from the date on which the advance is drawn and shall submit the mortgage bond, duly executed by the member, promptly to the Pay and Accounts Officer of the Council of States or, as the case may be, of the House of the People for examination before final record.

8. Safe custody and cancellation of mortgage bond.—(1) The mortgage bond shall be kept in the safe custody of the sanctioning authority.

(2) When the advance has been fully repaid, the bond shall be returned to the member concerned, duly cancelled, after obtaining a certificate from the Pay and Accounts Officer of the Council of States or, as the case may be, of the House of the People, as to the complete repayment of the advance and interest.

9. Insurance of conveyance.—The conveyance purchased from the advance shall be insured against full loss by fire, theft and accident and the insurance policy shall contain a clause (as in Form III) by which the insurance company agrees to pay to the Central Government instead of the owner, any sums payable in respect of loss or damage to the conveyance, which is not made good by repair, reinstatement or replacement.

## FORM I

(See rule 6)

Form of agreement to be executed at the time of drawing an advance for the purchase of a conveyance

An agreement made this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ One thousand nine hundred and eighty \_\_\_\_\_ between Shri \_\_\_\_\_ a Member of Parliament (hereinafter called the Borrower, which expression shall include his heirs, administrators, executors, legal representatives and \_\_\_\_\_ one part and the President of \_\_\_\_\_ called the Central Government) of the other Part: Whereas the Borrower has under the provisions of the Rules regulating the grant of advances to Members of Parliament for purchase of conveyance made under the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 applied to the Central Government for a loan of Rs. \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ only) for the purchase of a conveyance and the Central Government have agreed to lend the said amount to the Borrower on the terms and conditions hereinafter contained;

Now it is hereby agreed between the parties hereto that in consideration of the sum of Rs. \_\_\_\_\_ paid by the Central Government to the Borrower (the receipt of which the Borrower hereby acknowledges), the Borrower hereby agrees with the Central Government (1) to pay to the Central Government the said amount with interest calculated according to the said rules by monthly deductions from his salary as provided for by the said rules and hereby authorises the Central Government to make such



deductions and (2) to expend, within one month from the date of these presents, the full amount of the said loan in the purchase of a conveyance or if the actual price paid is less than the loan, to repay the difference to the Central Government forthwith and to execute a document hypothecating the said conveyance to the Central Government as security for the amount lent to the Borrower as aforesaid and interest thereon in the form provided by the said rules: And it is hereby Lastly agreed and declared that if the conveyance has not been purchased and hypothecated as aforesaid within one month from the date of these presents or if the Borrower within that period becomes insolvent or ceases to be a member or dies, the whole amount of the loan and interest accrued thereon shall become due and payable.

In witness whereof the Borrower has hereunto set his hand the day and year first before written.

Signed by the said Shri

in the presence of

## FORM II

(See rule 6)

### FORM OF MORTGAGE BOND FOR CONVEYANCE

THIS INDENTURE made this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ one thousand nine hundred and Eighty \_\_\_\_\_ BETWEEN \_\_\_\_\_ (hereinafter called "the Borrower", which expression shall include his heirs, administrators, executors, legal representatives and assignees) of the one part and the President of India (hereinafter called, the Central Government) of the other part; WHEREAS the Borrower has applied for and has been granted an advance of Rupees, . . . . . to purchase a conveyance in terms of Rules regarding the grant of advances to Members of Parliament for the purchase of conveyance made under the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (hereinafter referred to as "the said Rules") AND WHEREAS one of the conditions upon which the said advance has been/was granted to the Borrower is/was that the Borrower will/would hypothecate the said conveyance to the Central Government as security for the amount lent to the Borrower and WHEREAS the Borrower has purchased with, or partly with, the amount so advanced as aforesaid the conveyance particulars whereof are set out in the Schedule hereunder written.

NOW THIS INDENTURE WITNESSETH that in pursuance of the said agreement and for the consideration aforesaid the Borrower doth hereby covenant to pay to the Central Government the sum of Rs. . . . . aforesaid or the balance thereof remaining unpaid at the date of these presents by equal payment of Rs. . . . . each on the first day of every month and will pay interest on the sum for the time being remaining due and owing, calculated according to the said Rules and the Borrower doth agree that such

payments may be recovered by monthly deductions from his salary in the manner provided by the said Rules, and in further pursuance of the said agreement the Borrower doth hereby assign and transfer unto the Central Government the conveyance the particulars whereof are set out in the Schedule hereunder written by way of security for the said advance and the interest thereon as required by the said Rules.

And the Borrower doth hereby agree and declare that he has paid in full the purchase price of the said conveyance and that the same is his absolute property and that he has not pledged and, so long as any money remains payable to the Central Government in respect of the said advance, will not sell, pledge or part with the property in, or possession of, the said conveyance. Provided always and it is hereby agreed and declared that if any of the said instalments of principal or interest shall not be paid or recovered in manner aforesaid within ten days after the same are due or if the Borrower shall die or at any time ceases to be a Member or if the Borrower shall sell or pledge or part with the property in, or possession of, the said conveyance or become insolvent or make any composition or arrangement with his creditors or if any person shall take proceedings in execution of any decree or judgment against the Borrower, the whole of the said principal sum which shall then be remaining due and unpaid, together with interest thereon, calculated as aforesaid shall forthwith become payable AND IT IS HEREBY AGREED and declared that the Central Government may on the happening of any of the events herein before mentioned seize and take possession of the said conveyance and either remain in possession thereof without removing the same or else may remove and sell the said conveyance either by public auction or private contract and may out of the sale money retain the balance of the said advance then remaining unpaid and any interest due thereon calculated as aforesaid and all costs, charges, expenses and payments properly incurred or made in maintaining, defending or realizing its rights hereunder and shall pay over the surplus, if any to the Borrower his executors, administrators or personal representatives; PROVIDED FURTHER that the aforesaid power of taking possession or selling of said conveyance shall not prejudice the right of the Central Government to sue the Borrower or his personal representatives for the said balance remaining due and interest or in the case of the conveyance being sold the amount by which the net sale proceeds fall short of the amount owing; AND the Borrower hereby further agrees that so long as any moneys are remaining due and owing to the Central Government, he, the Borrower will insure and keep insured the said conveyance against loss or damage by fire, theft, and accident with an Insurance Company to be approved by the Accountant General concerned and will produce evidence to the satisfaction of the Accountant General that the Motor Insurance Company with whom the said motor vehicle is insured have received notice that the Central Government (President of India) is interested in the Policy

AND the Borrower hereby further agrees that he will not permit or suffer the said conveyance to be destroyed or damaged or to deteriorate in a greater degree than it would deteriorate by reasonable wear and tear

thereof and further that in the event of any damage or accident happening to the said conveyance the Borrower will forthwith have the same repaired and made good.

#### SCHEDULE

Description of Conveyance

Maker's name.

Description

No. of cylinders

Engine Number

Chassis No.

Cost Price.

IN WITNESS Where of the said (Borrower's name) and for and on behalf of the President of India have hereunto set their respective hands the day and year first above written.

Signed by the said  
in the presence of

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

(Signature of Witnesses)

(Signatures and Designation of the Borrower).

Signed by (name and designation).

for and on behalf of the President of India  
in the presence of

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

(Signatures of Witnesses)

(Signatures and Designation of the Officer).

Name and designation of the Borrower. \_\_\_\_\_

#### FORM III

(See rule 9)

#### Form of the clause to be inserted in Insurance Policies

1. It is hereby declared and agreed that Shri \_\_\_\_\_ (the owner of the conveyance hereinafter referred to as the insured in the Schedule to this policy) has hypothecated the conveyance to the Central Government (President of India) as security for advance for the purchase of the conveyance and it is further declared and agreed that the said Government (President) are interested in any moneys which but for this endorsement be payable to the said Shri \_\_\_\_\_ (the insured under this policy) in respect of the loss or damage to the said conveyance (which loss or damage is not made good by repair, reinstatement or replacement) and such moneys shall be paid to the said Government (President) as long as they are the mortgagees of the conveyance and their receipt shall be full and final discharge to the Company in respect of such loss or damage.

2. Save as by this endorsement expressly agreed, nothing herein shall modify or affect the rights or liabilities of the insured or the company respectively under or in connection with this policy or any term, provision or condition thereof.

[F. No. 2/1/MSA/85]

सा. का. नि. 13 (अ):—निम्नलिखित नियम, जो संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 (1954 का 30) की धारा 9 की धारा (1) के अधीन गठित संयुक्त समिति द्वारा केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् उक्त धारा की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं, तथा जिनका राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा उक्त धारा की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अनुमोदन और पुष्टि कर दी गई है, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

आवास और टेलीफोन सुविधा

(संसद सदस्य) सङ्गोघन नियम, 1986

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आवास और टेलीफोन सुविधा (संसद सदस्य) सङ्गोघन नियम, 1986 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आवास और टेलीफोन सुविधा (संसद सदस्य) नियम 1956 (जिन्हें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“2. सदस्यों को वास-सुविधा आदि की सुविधाएँ :—(1) प्रत्येक सदस्य अपने पूरे कार्यकाल तक फ्लैट के रूप में निशुल्क वास-सुविधा का हकदार होगा।

परन्तु यह कि जहाँ सदस्य को उसके अनुरोध पर बंगले के रूप में वास-सुविधा आवंटित की जाती है, वहाँ वह—

(क) पूरा सामान्य किराया संदत्त करेगा, यदि वह ऐसी वास-सुविधा का हकदार है; और



(ख) पूरा सामान्य किराया और पांच सौ रुपए प्रतिमास गैर-हकदारों प्रभार सदन करेगा। यदि वह इसका हकदार नहीं है।

स्पष्टीकरण (1) :—इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए 'फ्लैट' के अन्तर्गत होस्टल वास सुविधा है।

(2) प्रत्येक सदस्य, उप-नियम (1) के अधीन उसे आवंटित किसी वास-सुविधा के संबंध में, प्रति मास तीन सौ रुपए में अधिकतम की राशि के पाना और बिजली की निशुल्क प्रदाय का भी हकदार होगा।

(3) जहां, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट किसी वास-सुविधा के संबंध में, इसमें किए गए किसी सुधार या वृद्धि के कारण अथवा इसमें उपलब्ध कराई गई किसी अतिरिक्त सेवा के कारण किराया देय हो, वहां इस प्रकार के सुधार, वृद्धि या अतिरिक्त सेवा के संबंध में किराया की राशि देय सामान्य किराए से 25% कम होगी।

स्पष्टीकरण 1 :—इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए "सुधार या वृद्धि" से अतिरिक्त वास-सुविधा, फर्नीचर, टेबल और पैडमल, बंधो टेबल लैम्पो, ब्लौर स्टेण्डर्ड लैम्पो, बाथनरो, प्रशीतकोर्म, डेजर्टकूलरो और वातानुकूलन यूनितो की व्यवस्था अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2 :—"फर्नीचर" से फर्नीचर की ऐसी मदों अभिप्रेत है, जो किसी सदस्य को उसे आवंटित निवास-स्थान के लिए मिलती है और इस के अंतर्गत किसी सदस्य द्वारा अपने निवास-स्थान में किराया पर ली गई अतिरिक्त मदें भी हैं।

स्पष्टीकरण 3 :—"अतिरिक्त सेवा" से अभिप्रेत है :—

(क) सदस्यों के निवास-स्थानों में संबंध झाड़ूकों, जमादारों तथा कर्मचारियों को झाड़न और झाड़ू उपलब्ध कराना ;

(ख) सदस्यों को वास-सुविधाओं पर बिजली के बल्बों का प्रदाय ;

(ग) फूलों का क्यारियों का रख रखाव ;

(घ) सदस्यों के फायदे के लिए बनाए गए किर्मा स्थान (जैसे पूछताछ कार्यालय) का रख-रखाव, और

(ङ.) सदस्यों के फायदे के लिए उपलब्ध कराई गई कोई अन्य सुविधा।

3. उक्त नियमों के नियम 2क में "किराया की उसी दर पर जो सदस्य की मृत्यु के ठीक पूर्व उसके द्वारा संदेय था" शब्दों के स्थान पर "उम्मीद निबंधनों पर जो सदस्य की मृत्यु के ठीक पूर्व उसे लागू थे" शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियमों के नियम 4 में —

(क) उप-नियम (1) में

"सात हजार पांच सौ" शब्दों के स्थान पर "पन्द्रह हजार" शब्द रखे जाएंगे,

(ख) उप-नियम (3) में "सात हजार पांच सौ" शब्दों के स्थान पर "पन्द्रह हजार" शब्द रखे जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 4क में —

(क) उप-नियम (1) में

"पन्द्रह हजार" शब्दों के स्थान पर "तीस हजार" शब्द रखे जाएंगे,

(ख) उप-नियम (2) में "तीन हजार सात सौ पचास" और "सात हजार पांच सौ" शब्दों के स्थान पर "सात हजार पांच सौ" और "पन्द्रह हजार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उप-नियम (3) में "सात हजार पांच सौ" शब्दों के स्थान पर "पन्द्रह हजार" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तः स्थापित किया जाएगा :—

"(4) सदस्यों के ठीक काल बिल उपरोक्त तीस हजार काल प्रति वर्ष की, अधिकतम सीमा के धनीय मसतुल्य के भीतर समायोजित किए जा सकेंगे।"

6. उक्त नियमों के नियम 5 के पश्चात् में "उसके द्वारा अधिभाग किया जाता है," शब्दों के पश्चात् "एक निवास-स्थान के लिए" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

[फा स 4/1/एम.एम.ए. /85]

मुन्नाथ काश्यप महामन्त्रि

G.S.R. 13(E).—The following rules which have been made by the Joint Committee constituted under sub-section (1) of section 9 of the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954), after consultation with the Central Government, in exercise of the powers conferred on it by clause (f) of sub-section (3) of the said section, and have been approved and confirmed by the Chairman of the Council of States and the Speaker of the House of the People, as required by sub-section (4) of that section, are published for general information :—

### THE HOUSING AND TELEPHONE FACILITIES (MEMBERS OF PARLIAMENT) AMENDMENT RULES, 1986

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Amendment Rules, 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2. the following rule shall be substituted, namely :—

"2. Facilities of housing etc. to Members.—(1) Each members shall be entitled without payment of rent to housing accommodation in the form of a flat throughout his term of office :

Provided that where a member is allotted housing accommodation in the form of a bungalow at his request, he shall pay—

(a) full normal rent if he is entitled to such accommodation; and

(b) full normal rent and a non-entitlement charge of rupees five hundred per mensem, if he is not so entitled.

Explanation.—For the purposes of this sub-rule "flat" includes hostel accommodation.

(2) Every member shall, in respect of any accommodation allotted to him under sub-rule (1), also be entitled without payment of charges to the supply of water and electricity upto an amount not exceeding rupees three hundred per mensem.

(3) Where in respect of any accommodation referred to in sub-rule (1), rent is payable on account of any improvement or addition made to it or any additional service provided thereto, it shall be twenty-five per cent less than the normal rent payable in respect of such improvement, addition or additional service.

**Explanation I.**—For the purposes of this sub-rule “improvement or addition” means the provision of additional accommodation, furniture (table and pedestal fans, table lamps, floor standard lamps, boilers, refrigerators, desert coolers and air-conditioning units).

**Explanation II.**—“Furniture” means such items of furniture as are admissible to a member for a residence allotted to him and includes any additional items taken on rent by a member in his residence.

**Explanation III.**—“Additional service” means,

- (a) the provision of Sweepers, Janadars and the staff attached to members’ residences with dusters and brooms;
- (b) the supply of electric bulbs at the residences of members;
- (c) the maintenance of flower beds;
- (d) the maintenance of any place (like an Enquiry Office) intended for the common benefit of members; and
- (e) any other service provided for the common benefit of members.”

3. In rule 2A of the said rules, for the words “same rate of rent as was payable by”, the words “same terms as were applicable to” shall be substituted.

4. In rule 4 of the said rules,—

- (a) in sub-rule (1), for the words “seven thousand five hundred”, the words “fifteen thousand” shall be substituted;
- (b) in sub-rule (3), for the words “seven thousand five hundred”, the words “fifteen thousand” shall be substituted.

5. In rule 4A of the said rules —

- (a) in sub-rule (1) for the words “fifteen thousand”, the words “thirty thousand” shall be substituted
- (b) in sub-rule (2), for the words “three thousand seven hundred fifty” and “seven thousand five hundred”, the words “seven thousand five hundred” and “fifteen thousand” shall, respectively, be substituted;
- (c) in sub-rule (3), for the words “seven thousand five hundred”, the words “fifteen thousand” shall be substituted;
- (d) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

“(4) The trunk call bills of the members may be adjusted within the monetary equivalent of the ceiling of thirty thousand local calls per annum as aforesaid”

6. In rule 5 of the said rules, in the proviso, after the words “of rent” the words “for one of the residences” shall be inserted.

[F. No. 4/1/MSA/85]

SUBHASH C. KASHYAP, Secretary-General